एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

मार्च 2016
खंड XXX अंक I

इस अंक में

4 अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोगः संभावनाओं की तलाश
5 एक्ट ईस्टः सीएलएमवी क्षेत्र की पड़ताल
6 वैश्विक जैविक बाजार
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 तिमाही गतिविधियां
9 सुर्खियों में एक्ज़िम बैंक
10 भारतीय चमड़ा उद्योग
11 पश्चिम बंगाल की निर्यात रणनीति
12 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां और पुस्तक समीक्षा
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा जगत
15 स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान
16 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
17 भारतीय व्यापार का प्रदर्शन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

फोकस अफ्रीकाः दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (सैडेक) के साथ भारत का कारोबार बढ़ाना

दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी- सैडेक) की स्थापना 1980 में हुई थी, जब सात अफ्रीकी देशों (अंगोला, बोत्सवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, तंजानिया और जांबिया) के एक गठबंधन के रूप में इसकी नींव रखी गई थी. तब इसे दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन (एसएडीसीसी) के रूप में जाना जाता था. इसका प्रमुख उद्देश्य था- दक्षिणी अफ्रीका का राजनीतिक उदारीकरण.

फिर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के दौरान इस संगठन ने 17 अगस्त 1992 को एक समन्वय सम्मेलन से विकास समुदाय का रूप लिया. यह इतिहास लिखा गया नामीबिया के विंधोएक में, जब राष्ट्रप्रमुखों और सरकार प्रमुखों के सम्मेलन में सैडेक संधि और घोषणा पर हस्ताक्षर हुए और इस तरह इस संगठन को कानूनी रूप दे दिया गया. ढांचे के साथ उद्देश्य भी बदल गया. अब इसका उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के साथ महाद्वीप में उनका आर्थिक समावेश भी हो गया था.

समय के साथ बढ़ती नई चुनौतियों और संस्थागत सुधारों की जरूरत के मद्देनजर 14 अगस्त, 2001 को इस संधि में संशोधन हुआ. आज सैडेक में 15 सदस्य देश हैं- अंगोला, बोत्सवाना, कांगो, लेसोथो, मैडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जांबिया और जिम्बाब्वे. सैडेक आज अफ्रीका महाद्वीप का अभिन्न हिस्सा है, जो पूरे अफ्रीका के 32.5 प्रतिशत भू-भाग में फैला है. अफ्रीका की 27.7 प्रतिशत आबादी सैडेक में ही बसती है. अफ्रीकी क्षेत्र की जीडीपी में ईकोवास के बाद सैडेक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है. 2014 में उप सहारीय अफ्रीका की सांकेतिक जीडीपी में इसका 37 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि अफ्रीका की जीडीपी में 27.9 प्रतिशत और विश्व की जीडीपी में 0.8 प्रतिशत योगदान रहा.

2014 में सैडेक की औसत आर्थिक विकास दर 4.6 प्रतिशत थी, जो बीते वर्ष यानी 2013 की 5.4 प्रतिशत के मुकाबले कम थी. कारण था- दो सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं दक्षिण अफ्रीका और अंगोला की विकास दर धीमी रहना. दक्षिण अफ्रीका की विकास दर जहां अधिक खनन और उसकी मुद्रा 'रैंड' के कमजोर होने से धीमी रही, वहीं अंगोला को तेल क्षेत्र में आई गिरावट के चलते मंदी का सामना करना पड़ा.

2014 के मध्य से वैश्विक आर्थिक परिवेश में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भी इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है. जून 2014 के बाद से तेल की कीमतें गिरी हैं. मांग और आपूर्ति के सिद्धांत ने भी अपना काम किया है. सैडेक की संयुक्त जीडीपी 2013 की 687.7 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2014 में 686.8 बिलियन यूएस डॉलर रही. **(टेबल देखें)**

सैडेक क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं और उनके आकार में भी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी 2014 में 350.1 बिलियन यूएस डॉलर की रही, जो सैडेक क्षेत्र की बाकी 14 अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी को मिलाकर भी उससे ज्यादा रही। बाकी 14 की जीडीपी 336.7 बिलियन यूएस डॉलर रही।

सैडेक देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार

सैडेक के वैश्विक व्यापार में हाल के वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो सैडेक अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते वैश्वीकरण को प्रदर्शित करती है. 2004 से 2014 की अवधि के दौरान सैडेक का कुल व्यापार तीन गुना बढ़ गया. 2004 में यह 137 बिलियन यूएस डॉलर था जो इस अवधि के दौरान 11 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ते हुए 2014 में 410.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. वैश्विक व्यापार की बात की जाए तो एक ब्लॉक के रूप में सैडेक का प्रदर्शन स्थिर रहा है. वैश्विक व्यापार में सैडेक का हिस्सा 2004 के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 1.1 प्रतिशत हो गया. हालांकि, अफ्रीका के कुल व्यापार में सैडेक का हिस्सा गिरा है, जो 2004 के 41 प्रतिशत से 2014 में 34.8 प्रतिशत रह गया.

वहीं, निर्यात के मामले में सैडेक का कुल निर्यात 2004 के 61 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014 में 208.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इसके साथ ही इस अवधि के दौरान वैश्विक निर्यात में सैडेक का हिस्सा 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया. जहां तक आयात की बात है तो आयात भी 2004 के 76 बिलियन यूएस डॉलर (वैश्विक आयात का 0.8 प्रतिशत) से बढ़कर 2014 में 202.4 बिलियन यूएस डॉलर (वैश्विक आयात का 1.1 प्रतिशत) हो गया.

इस दशक के दौरान, सैडेक का व्यापार शेष 2004 के 15 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे से 2014 में 5.9 बिलियन यूएस

टेबलः सैडेक देशों के मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े

(देश/क्षेत्र	सांकेतिक जीडीपी (यूएस बिलियन डॉलर)			वास्तविक जीडीपी (%)			प्रति व्यक्ति जीडीपी (यूएस बिलियन डॉलर)			उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (औसत %)			जनसंख्या (मिलियन)		
	2013	2014[आ]	2015[अ]	2013	2014[आ]	2015[अ]	2013	2014[आ]	2015[अ]	2013	2014[आ]	2015[अ]	2013	2014[आ]	2015[अ]
अंगोला	124.2	129.3	102.0	6.8	4.8	3.5	5245.4	5303.9	4061.8	8.8	7.3	10.3	23.7	24.4	25.1
बोत्सवाना	15.1	15.2	13.1	9.3	4.4	2.6	7261.0	7233.1	6149.7	5.8	3.9	4.0	2.1	2.1	2.1
कांगो	32.7	35.9	39.1	8.5	9.2	8.4	424.4	452.9	478.2	0.8	1.0	1.0	77.0	79.3	81.7
लेसोथो	2.3	2.2	2.0	3.6	3.4	2.6	1194.7	1161.7	1062.6	5.0	3.8	3.9	1.9	1.9	1.9
मैडागास्कर	10.6	10.7	9.5	2.3	3.3	3.4	462.5	452.8	392.6	5.8	6.1	7.6	22.9	23.6	24.2
मलावी	5.4	6.1	6.4	5.2	5.7	4.0	317.5	344.0	352.7	28.3	23.8	20.1	17.1	17.6	18.1
मॉरीशस	11.9	12.6	11.6	3.2	3.6	3.2	9476.5	9999.3	9186.5	3.5	3.2	2.0	1.3	1.3	1.3
मोजाम्बिक	15.6	16.7	17.0	7.4	7.4	7.0	604.7	629.8	626.2	4.2	2.3	4.0	25.8	26.5	27.1
नामीबिया	12.9	13.6	12.9	5.1	4.5	4.8	5955.3	6188.1	5787.2	5.6	5.3	4.8	2.2	2.2	2.2
सेशेल्स	1.4	1.4	1.4	6.0	3.3	3.5	15187.0	15140.7	14466.2	4.3	1.4	4.3	0.1	0.1	0.1
दक्षिण अफ्रीका	366.2	350.1	317.3	2.2	1.5	1.4	6889.7	6482.8	5783.5	5.8	6.1	4.8	53.2	54.0	54.9
स्वाजीलैंड	4.6	4.4	4.3	2.9	2.5	1.9	4178.0	3994.2	3847.7	5.6	5.7	5.2	1.1	1.1	1.1
तंजानिया	44.4	48.1	46.2	7.3	7.0	6.9	969.1	1028.8	968.8	7.9	6.1	5.6	45.8	46.7	47.7
जांबिया	26.8	26.6	24.5	6.7	5.6	4.3	1845.4	1771.6	1576.4	7.0	7.8	7.3	14.5	15.0	15.5
जिम्बाब्वे	13.5	13.8	13.9	4.5	3.3	1.4	1028.5	1043.1	1037.2	1.6	-0.2	-1.6	13.1	13.3	13.4
सैडेक	**687.7**	**686.8**	**621.0**	**5.4***	**4.6***	**3.9***	**2278.8#**	**2222.1#**	**1962.4#**	**6.7***	**5.6***	**5.6***	**301.8**	**309.1**	**316.5**

नोट : आ- आकलन, अ- पूर्वानुमान, *-सामान्य औसत, #- भारित औसत

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकनोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2015, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

डॉलर के अधिशेष तक पहुंच गया. यह परिवर्तन प्रमुख रूप से अंगोला के कारण हुआ, जिसने 2014 में 37.2 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया. क्षेत्र की अन्य अर्थव्यवस्थाओं कांगो, स्वाजीलैंड, जांबिया और बोत्सवाना ने भी वर्ष के दौरान अधिशेष दर्ज किया.

सैडेक देशों में दक्षिण अफ्रीका और अंगोला सबसे बड़े निर्यातक देश रहे. 2014 में इन दोनों का निर्यात सैडेक के कुल निर्यात का 74 प्रतिशत रहा. क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात (खनिज ईंधन) क्रूड पेट्रोलियम का किया गया, जिसका निर्यात सैडेक के कुल निर्यात का 36 प्रतिशत रहा. निर्यात की गई प्रमुख चीजों में इसके बाद मोती और बहुमूल्य रत्नों, अयस्क और धातुमल, कॉपर और कॉपर की चीजों, वाहनों, लोहा, स्टील और मशीनरी का स्थान रहा. 2014 में सैडेक से निर्यात का प्रमुख बाजार चीन, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड रहे.

आयात की बात की जाए तो सैडेक में प्रमुख आयातक देश दक्षिण अफ्रीका और अंगोला हैं। 2014 में दोनों का आयात मिलाकर सैडेक के कुल निर्यात का 62.5 प्रतिशत रहा. क्रूड पेट्रोलियम और मशीनरी सबसे ज्यादा आयात की गई. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रिकल उपकरणों, वाहनों, प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान, लोहा या स्टील और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का स्थान रहा. 2014 में चीन सैडेक को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी का स्थान रहा. 2014 में भारत सैडेक का चौथा सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा, जिसका हिस्सा 5.3 प्रतिशत रहा.

सैडेक देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

निर्यात और आयात दोनों के लिहाज से सैडेक भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है. आर्थिक और व्यापार संपर्क तथा आर्थिक रिश्तों में बढ़ती सरगर्मी से व्यापार में मात्रात्मक विस्तार हुआ है. पिछले दस वर्षों के दौरान सैडेक देशों के साथ भारत का कुल व्यापार आठ गुना वृद्धि करते हुए 2004 के 3.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014 में 29.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया. वहीं, सैडेक देशों को भारत का कुल निर्यात 2004 के 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014 में 15 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. इस अवधि के दौरान इसमें नौ गुना वृद्धि दर्ज की गई. सैडेक से भारत का कुल आयात भी बढ़ा. हालांकि इसकी रफ्तार निर्यात की तुलना में कुछ धीमी रही, जो 2 बिलियन यूएस डॉलर से सात गुना बढ़कर 14.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा. लगातार छह वर्षों तक घाटा दर्ज करने के बाद सैडेक के साथ भारत का व्यापार शेष 2014 में 0.4 बिलियन यूएस डॉलर के अधिशेष में बदल गया.

सैडेक के व्यापार भागीदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 2014 में सैडेक के वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा 7.4 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 7 प्रतिशत रहा. सैडेक क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि 2014 में भारत के वैश्विक निर्यात का 4.7 प्रतिशत और भारत के वैश्विक आयात का 3.2 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र का रहा.

सैडेक देशों में विदेशी निवेश

सैडेक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रमुख रूप से संसाधन आधारित रहा है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2015 के अनुसार, सैडेक क्षेत्र में एफडीआई आवक 2004 की 5.6 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2014 में 16 बिलियन यूएस डॉलर रही. 2014 में सैडेक क्षेत्र में एफडीआई अफ्रीका को कुल एफडीआई आवक की लगभग 30 प्रतिशत रही. सैडेक को एफडीआई आवक के मामले में दक्षिण अफ्रीका और मोजांबिक दो प्रमुख देश रहे. 2014 में एफडीआई आवक के मामले में जांबिया, तंजानिया और कांगो प्रमुख रहे.

सैडेक से एफडीआई जावक 2013 के 13.2 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2014 में गिरकर 9.2 बिलियन यूएस डॉलर रही. सैडेक से एफडीआई जावक प्रमुख रूप से दक्षिण अफ्रीका और अंगोला को रही.

सैडेक देशों के साथ भारत के निवेश संबंध

सैडेक क्षेत्र में भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्यमों ने विनिर्माण, खनन, निर्माण और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों उपक्रमों में निवेश किया है. वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सैडेक क्षेत्र में भारत का अनुमोदित संचयी निवेश अप्रैल 1996 से मार्च 2015 तक 46.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा. इस क्षेत्र में भारत का सबसे ज्यादा निवेश मोजांबिक और दक्षिण अफ्रीका में हुआ. सैडेक में भारत का निवेश अफ्रीका में कुल भारतीय निवेश का लगभग 93 प्रतिशत रहा.

अफ्रीका में भारतीय निवेश परंपरागत रूप से मॉरीशस में केंद्रित रहा है. वजह है वहां की विदेशी वित्तीय सुविधाएं और आसान कर शर्तें. हालांकि भारतीय निवेशक इस क्षेत्र के अन्य देशों में भी निवेश कर रहे हैं. सैडेक क्षेत्र से भारत में एफडीआई आवक भी मॉरीशस से ही सबसे ज्यादा है, जो भारत की कुल एफडीआई आवक की 35.2 प्रतिशत है. अप्रैल 2000 से मार्च 2015 के दौरान इस क्षेत्र से भारत को एफडीआई आवक 88 बिलियन यूएस डॉलर रही.

सैडेक देशों से व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने में एक्ज़िम बैंक के प्रयास

सैडेक क्षेत्र के देश भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के लिए हमेशा से केंद्र में रहे हैं और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के संवर्द्धन तथा सहयोग के लिए बैंक की रणनीति का भी एक अहम पहलू हैं. बैंक सैडेक क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार एवं निवेश संबंधों के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए विभिन्न वित्तपोषण, सलाहकारी सेवाएं और सहयोग कार्यक्रम प्रदान करता है. क्षेत्र में प्रदान किए गए एक्ज़िम बैंक के वित्तीय कार्यक्रमों में ऋण-व्यवस्थाएं, परियोजना निर्यात के लिए वित्त, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता ऋण और विदेशी निवेश वित्त के साथ-साथ अफ्रीका में परियोजना विकास कंपनी (पीडीसी) की स्थापाना भी शामिल है. दक्षिण अफ्रीका के जोहांस्बर्ग और इथियोपिया के अदिस अबाबा स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय सैडेक क्षेत्र के साथ आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और बैंक की विभिन्न पहलों के साथ करीब से जुड़े हुए हैं.

सैडेक देशों में भारत के लिए निवेश के अवसर

सैडेक अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में सबसे ज्यादा संसाधन बहुल हैं. सैडेक के लिए अन्य के साथ-साथ ढांचागत विकास, कृषि और कृषि प्रसंस्करण, खनन, विनिर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं. इस क्षेत्र में विकास कम होने का प्रमुख कारण सीमित निवेश है. इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र में भारत के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को बैंक ने अपने अध्ययन में चिह्नित किया है.

सैडेक क्षेत्र के देश भारत के लिए व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभर रहे हैं और उन देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी उनके ढांचागत विकास और आर्थिक तरक्की के प्रयासों में भी सहायक होगी. इसके लिए भारत उन देशों के साथ क्षमता निर्माण संबंधी अनुभव साझा कर सकता है. साथ ही सैडेक सदस्य देशों में विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में निवेश सैडेक सदस्य देशों में भारत की मौजूदगी को बढ़ाने और लंबी अवधि के वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने में रणनीतिक महत्व का साबित होगा.

सीआईआई-एक्ज़िम बैंक इंडिया-अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप कॉन्क्लेव

भारतीय एक्ज़िम बैंक हर साल होने वाली सीआईआई-एक्ज़िम बैंक इंडिया-अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का महत्वपूर्ण भागीदार है. इंडिया-अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर 11वीं सीआईआई-एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव 14-15 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में हुई थी.

कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल (रिटायर्ड) वी.के. सिंह ने कहा कि भारत के आर्थिक पुनरुत्थान का अफ्रीका की विकास पहलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा. जनरल सिंह ने इंडिया- अफ्रीका पार्टनरशिप के लिए पारस्परिक सहयोग को जरूरी बताते हुए सतत विकास, क्लीन टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया.

14 मार्च, 2016 को उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल सिंह, घाना के माननीय उपराष्ट्रपति श्री क्वेसी अमीसाह आर्थर, दक्षिण सूडान के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जेम्स वानी इग्गा और नाइजीरिया के माननीय उद्योग, व्यापार और निवेश मंत्री श्री ओकेचुकवु एनालमा के करकमलों से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का अध्ययन 'फोकस अफ्रीकाः दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (सैडेक) के साथ भारत के व्यापार का संवर्द्धन' शीर्षक नामक अध्ययन जारी किया गया.

इस सम्मेलन के जरिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत भारत और अफ्रीकी कारोबारियों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तालमेल बनाने में मदद मिली। यह सम्मेलन वरिष्ठ मंत्रियों, नीति निर्माताओं और भारत व अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारी अगुआओं के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक रहा.

सौर उद्योग अभी नया है और इसमें भरपूर अवसर हैं. अपार संभावनाओं और अवसरों तथा भौगोलिक और सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद सौर ऊर्जा को विकसित करने में विभिन्न देशों में वैभिन्नय है।

इस परिस्थिति में सौर असंतुलन बनने का जोखिम है. यानी ऐसी परिस्थिति जहां विकासशील और अल्प विकसित देशों को सौर ऊर्जा का वैसा लाभ नहीं मिल पाएगा, जैसा विकसित देशों को मिल रहा है. यह विरोधाभासी स्थिति होगी कि सौर संसाधनों की बहुलता वाले देश ही अपने संसाधनों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होंगे, जबकि अल्प सौर संसाधन वाले देश ज्यादा लाभ उठाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग

इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने 2015 में फ्रांस में कॉप21 (सीओपी21) के दौरान कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सौर संसाधन बहुल 121 देशों के गठबंधन के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग की नींव रखी. इस गठबंधन का उद्देश्य इन देशों में सौर ऊर्जा का विकास करना है.

इनमें से ज्यादातर देशों की भौगोलिक ऐसी स्थिति है कि जहां सूरज साल में 300 दिन खिलता है और सूरज की किरणों से सस्ती सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है. हालांकि सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्रोत की आसान उपलब्धता और बहुलता ही पर्याप्त नहीं है. यद्यपि इन सभी चिह्नित देशों में रेडिएशन का उच्च स्तर है, फिर भी ज्यादातर अवसरों को भुनाया नहीं जा सका है. कुछ देशों में स्पष्ट अक्षय ऊर्जा नीति का अभाव और साथ ही इसे लागू करने के लिए मजबूत ढांचे की कमी जैसी कुछ ढांचागत समस्याएँ है .

आईएसए मैट्रिक्स ढांचा

जैसा कि कॉप21 सदस्य देशों में स्पष्ट है कि वे सभी आर्थिक विकास के अलग-अलग चरणों में हैं, इसलिए सौर प्रौद्योगकी को अपनाने की संभाव्यता भी अलग है.

इस वैविध्यपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईएसए सदस्य देशों के लिए एक सहयोग ढांचा बनाया जा सकता है. इस ढांचे में देशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, ताकि सभी देश आईएसए के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक-दूसरे की मजबूती का लाभ उठाते हुए एक-दूसरे से मिलकर काम कर सकें.

इस ढांचे को चार-चार के चार हिस्सों में बांटा जा सकता है. पहले चतुर्थांश में तकनीक रूप से दक्ष देश हैं, जो तकनीक के मामले में सबसे ऊपर हैं और सौर किरणों से अधिकतम ऊर्जा हासिल करने के लिए लगातार शोध एवं विकास कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नवोन्मेष की लागत ज्यादा होती है और उसमें जोखिम भी रहता है. यही वजह है कि नवोनन्मेष की ज्यादातर गतिविधियां विकसित देशों में ही होती हैं.

दूसरा चतुर्थांश सौर उपकरणों के विनिर्माण पर केंद्रित है, जहां उभरते देशों ने अहम प्रगति की है. ये ऐसे देश हैं जो सौर उपकरण विनिर्माण में सक्षम हैं और न सिर्फ अपनी घरेलू मांग को पूरा करते हैं, बल्कि निर्यात भी करते हैं. प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में ये देश भी तरक्की कर रहे हैं.

तीसरे चतुर्थांश में बहुत से ऐसे आईएसए देशों के अवसर हैं जो लागत के मामले में निचले पायदान पर हैं. ये आईएसए देश नए विनिर्माण और असेंबली केंद्र हैं. मांग बढ़ने और बढ़ती विनिर्माण क्षमता के साथ इन केंद्रों के लागत श्रृंखला में ऊपर आने उम्मीद है.

एक्ज़िबिटः सहयोग चक्र

अंतिम चतुर्थांश बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से सहयोग के इस ढांचे में महत्वपूर्ण है. ये ऐसे देश हैं जहां या तो बिजली पूरी तरह पहुंची ही नहीं है और इनमें से ज्यादातर अल्प विकसित हैं या फिर ऐसे देश जहां ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की भारी मांग है. ऐसी स्थिति आईएसए के ज्यादातर विकासशील देशों में है.

निष्कर्ष

विश्व सौर पीवी की स्थापना 2004 के 3.4 गीगावाट से 2014 में बढ़कर 179.6 गीगावाट हो गई है. सौर ऊर्जा में यह बढ़ोत्तरी महाद्वीपों और उभरते तथा विकासशील देशों के लिए सौर ऊर्जा जरूरतें पूरी करने और हरित निवेश अवसरों के लिए एक कसौटी है.

सौर परियोजना विकास के आरंभिक चरण में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली की जरूरत है. इसके साथ ही आगे के चरणों में निजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए कारोबार के अवसर बढ़ाने की भी जरूरत है.

आकलन है कि दुनियाभर में सौर स्रोतों से स्थापित नवीनतम क्षमता अगले दो-चार साल में दोगुनी हो सकती है. इस स्थिति को नवोन्मेषी वित्तपोषण और प्रोत्साहन कार्यप्रणालियों द्वारा हासिल किया जा सकता है. हालांकि बहुत से देशों में अनुकूल नीतियां पहले ही लागू की जा चुकी हैं, फिर भी नीतिगत प्रयासों को और उच्चतम स्तर पर ले जाने की जरूरत है, ताकि सौर ऊर्जा विकास में बढ़त जारी रखी जा सके. आईएसए की भूमिका यहीं महत्वपूर्ण हो जाती है. आईएस लाभप्रद भागीदारियों के जरिए दुनियाभर में सौर प्रौद्योगिकी के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकता है.

कंबोडिया, लाओ, म्यांमार और वियतनाम मिलकर सीएलएमवी देश बनते हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) का अभिन्न हिस्सा हैं. आसियान के कुल भौगौलिक हिस्से में से 32 प्रतिशत में यही देश हैं. इन देशों में आसियान की 26 प्रतिशत आबादी बसती है और 2014 में आसियान की कुल जीडीपी **(टेबल-1)** में 12 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों का रहा था. ये देश केंद्रीय आयोजना से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं. सीएलएमवी देश प्राथमिक रूप से कृषि पर आधारित हैं. हाल के वर्षों में यहां थोड़ा-बहुत आर्थिक स्थायित्व आया है और भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं. सीएलएमवी अर्थव्यवस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रम से विपुल हैं, लेकिन उन्हें अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का सामना करना पड़ रहा है.

पहला सीएलएमवी सम्मेलन नवंबर 2004 में लाओ के वियंतिआन में हुआ था. यहां सीएलएमवी देशों में आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वियंतिआन घोषणापत्र को अंगीकार किया गया. इस घोषणापत्र के अनुसार, सहयोग के सात क्षेत्र चिह्नित किए गए थे. इनमें व्यापार और निवेश, कृषि, उद्योग और ऊर्जा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और मानव संसाधन विकास शामिल हैं. यह घोषणापत्र सहयोग को मजबूत करने एवं बढ़ाने और क्षेत्रीय एकता के संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

सीएलएमवी देशों में वियतनाम का व्यापार सबसे ज्यादा है. इसके बाद म्यांमार और कंबोडिया का स्थान आता है, जबकि लाओ का विदेश व्यापार काफी कम है. वियतनाम और कंबोडिया के लिए व्यापार का खुलापन (2014 में क्रमशः 180.9 प्रतिशत और 152.9 प्रतिशत) जो कुल व्यापार को जीडीपी से विभाजित कर मापा जाता है, काफी उच्च है. जबकि 2014 में ही लाओ के लिए व्यापार जीडीपी अनुपात 92.1 प्रतिशत और म्यांमार के लिए 72.6 प्रतिशत रहा था. सीएलएमवी देशों का व्यापार घाटा (22.7 बिलियन यूएस डॉलर) बना रहा, जो क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए पूंजीगत माल के आयात के चलते रहा.

हाल के वर्षों में, सीएलएमवी क्षेत्र में एफडीआई आवक बढ़ी है, जिसका इस क्षेत्र को लाभ मिला है, प्राथमिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को. म्यांमार पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध हटने से वहां भी निवेश आवक बढ़ी है, विशेष रूप से चीन, कोरिया और थाईलैंड से. सीएलएमवी क्षेत्र में 2014 में एफडीआई आवक 12.6 बिलियन यूएस डॉलर रही, जो 2004 में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर ही थी **(टेबल 2)**. यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों को निवेश के अवसर मुहैया कराता है.

भारत द्वारा 1992 में लुक ईस्ट (अब एक्ट ईस्ट) नीति को अपनाना आसियान देशों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित करने की दिशा में एक पहल थी. तब से अब तक भारत ने एक वार्ताकार भागीदार से रणीनीतिक भागीदार बनने का सफर तय किया है. आर्थिक और व्यापारिक संबंधों से व्यापार की मात्रा तो बढ़ी ही है, ये आर्थिक रिश्ते की गर्माहट को भी प्रदर्शित करते हैं. बीते दस वर्षों के दौरान सीएलएमवी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 2004 के 1.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014 में 11.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो दस गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है. भारत ने सीएलएमवी देशों के साथ 2014 में 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस बनाए रखा. सीएलएमवी देशों में भारत म्यांमार को छोड़कर सभी के साथ व्यापार सरप्लस बनाए रखता है. म्यांमार के साथ व्यापार घाटे की मुख्य वजह दालों और वन्य उत्पादों का आयात है. सीएलएमवी देशों को भारत के निर्यात में फार्मास्युटिकल्स, मशीनरी और उपकरण, रेलवे के अलावा अन्य वाहन, प्लास्टिक और कॉटन शामिल हैं. वहीं, भारत इस क्षेत्र से रबर, लकड़ी और लकड़ी का सामान, अयस्क, स्लैग और भस्म, खनिज ईंधन, कॉफी, चाय और मसाले आयात करता है.

सीएलएमवी देशों में संयुक्त उपक्रमों और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों में भारत का अनुमोदित प्रत्यक्ष निवेश 2014-15 के दौरान 26.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा था. इसमें से 79.6 प्रतिशत जावक वियतनाम को ही रही.

टेबल 1: सीएलएमवी देशों के मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े

देश/क्षेत्र	जनसंख्या, 2014	जीडीपी 2014	जीडीपी विकास दर (%)		निर्यात 2014	आयात 2014	व्यापार शेष
	मिलियन	बिलियन यूएस डॉलर	2013	2014	बिलियन यूएस डॉलर	बिलियन यूएस डॉलर	बिलियन यूएस डॉलर
कंबोडिया	15.3	16.6	7.4	7.0	12.0	13.3	-1.2
लाओ पीडीआर	6.9	11.7	8.0	7.4	3.8	6.8	-3.0
म्यांमार	51.4	63.1	8.4	8.5	23.9	21.9	2.0
वियतनाम	90.6	185.9	5.4	6.0	157.9	178.4	-20.5
सीएलएमवी	**164.3**	**277.3**	**7.3**	**7.2**	**197.7**	**220.4**	**-22.7**
आसियान	**621.0**	**2518.4**	**5.2**	**4.7**	**1317.5**	**1272.9**	**44.6**
आसियान में सीएलएमवी का हिस्सा (%)	*26.5%*	*11.0%*	-	-	*15.0%*	*17.3%*	-

-लागू नहीं, स्रोतः आईएमएफ, ट्रेड मैप, आईटीसी जेनेवा, एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

टेबल 2: सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश का परिदृश्य (यूएस मिलियन डॉलर)

देश/क्षेत्र	2004	2009	2012	2013	2014
कंबोडिया	131.4	928.4	1835.2	1871.7	1730.4
लाओ पीडीआर	17.0	189.5	294.4	426.7	720.8
म्यांमार	729.9	27.2	496.9	584.3	946.2
वियतनाम	1610.0	7600.0	8368.0	8900.0	9200.0
सीएलएमवी	**2488.3**	**8745.0**	**10994.5**	**11782.7**	**12597.4**
आसियान	**40151.0**	**46084.0**	**108096.0**	**126037.0**	**132833.0**
आसियान में सीएलएमवी का हिस्सा	*6.2%*	*19.0%*	*10.2%*	*9.3%*	*9.5%*

स्रोतः विश्व निवेश रिपोर्ट 2015, अंकटाड, एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

वैश्विक जैविक बाजार

जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान (एफआईबीएल) एवं जैविक कृषि आंदोलन अंतरराष्ट्रीय महासंघ (आईएफओएएम) द्वारा आयोजित नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की लगभग 43.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि का प्रबंधन जैविक रूप से किया जा रहा था. जैविक प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली भूमि वर्ष 1999 में मात्र 11 मिलियन हेक्टेयर थी जिसमें वर्ष 2013 तक काफी वृद्धि हुई.

जैविक मानक रखने वाले देशों की संख्या बढ़कर 86 हुई है और इसके अतिरिक्त 26 अन्य देश हैं जो विधि निर्माण के प्रारूपण की प्रक्रिया में हैं. प्रमाणन समितियों की संख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. वर्ष 2011 में प्रमाणन समितियों की कुल संख्या 549 थी, जो वर्ष 2012 में बढ़कर 576 हो गई. अधिकांश प्रमाणन समितियां यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, भारत और कनाडा में स्थापित हैं. एशिया में इस समय यूरोप की तुलना में अधिक प्रमाणन समितियां हैं.

वैश्विक स्तर पर ओशिनिया इस समय जैविक कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि के मामले में सबसे आगे है तथा इसने कुल जैविक कृषि भूमि में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान दिया है. वर्ष 2013 में यूरोप के पास कुल जैविक कृषि भूमि का 27 प्रतिशत भाग था जो कि वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि के लिए दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है. वर्ष 2013 में ही लैटिन अमेरिका लगभग 6.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि का जैविक प्रबंधन कर विश्व की कुल जैविक कृषि भूमि का 15 प्रतिशत का भागीदार रहा. वर्ष 2013 में उत्तरी अमेरिका ने जैविक खेती के अंतर्गत वैश्विक क्षेत्र की लगभग 7 प्रतिशत भूमि का प्रतिनिधित्व किया. एशिया के पास जैविक कृषि हेतु 3.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी जो विश्व की कुल जैविक भूमि का लगभग 8 प्रतिशत थी. अफ्रीका 1.2 मिलियन हेक्टेयर के साथ विश्व की जैविक कृषिगत भूमि का 3 प्रतिशत भाग समेटे रहा. देशानुसार, ऑस्ट्रेलिया के पास जैविक प्रबंधन के तहत सबसे बड़ा भूभाग था, जिसके बाद अर्जेंटीना, अमेरिका, चीन, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, उरुग्वे और कनाडा का स्थान रहा.

संयुक्त राज्य अमेरिका

स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के चलते अमेरिका में जैविक खाद्य पदार्थों की खपत काफी बढ़ी है. न्यूट्रिशन बिज़नेस जर्नल के अनुसार वर्ष 2006 में अमेरिका में जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री 15.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो 8 साल बाद (2014 में) बढ़कर 34.8 बिलियन यूएस डॉलर (यानी दोगुनी से भी ज्यादा) हो गई. अमेरिका में विभिन्न श्रेणियों के जैविक खाद्य पदार्थों के बीच जैविक फल और सब्जियां प्रमुख वस्तुएं हैं जिनकी बिक्री वर्ष 2014 में ही लगभग तीन गुना बढ़कर 15.1 बिलियन डॉलर जा पहुंची. जैविक / ऑर्गेनिक डेयरी अमेरिका में ऑर्गेनिक फूड / जैविक खाद्य समूह में दूसरा सबसे बड़ा अनुभाग है, जो कुल डेयरी उत्पादन का 6 प्रतिशत है.

यूरोप

एफआईबीएल तथा आईएफओएएम के अनुसार वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद विश्व में जैविक उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जिसकी वैश्विक जैविक बाजार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. वर्ष 2013 में यूरोप का जैविक बाजार 24.3 बिलियन यूरो मूल्य का था, जबकि उसी साल पूरे यूरोपीय संघ के जैविक बाजार का कुल मूल्य 22.2 बिलियन यूरो रहा था.

वर्ष 2013 में यूरोप में जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार जर्मनी रहा, जिसकी हिस्सेदारी समूचे यूरोपीय संघ के जैविक उत्पादों में 31.3 प्रतिशत थी. यूएसडीए की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जैविक खाद्य पदार्थों की मंडी जर्मनी ही है. वर्ष 2013 में जर्मनी के जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री 7.55 बिलियन यूरो की रही, जो जर्मनी के कुल खाद्य पदार्थों की बिक्री का 4 प्रतिशत थी.

फ्रांस का जैविक बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में भी इससे ऐसी ही अपेक्षा है. वर्ष 2013 में फ्रांस के जैविक बाजार की कीमत 4.4 बिलियन यूरो थी, जो वर्ष 2012 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक थी. फ्रेंच जैविक बाजार में वर्ष 2005 से 2013 के दौरान 13.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई और जैविक बाजार की कीमत भी 1.6 बिलियन यूरो से बढ़कर 4.4 बिलियन यूरो तक जा पहुंची.

एफआईबीएल के प्रकाशन 'वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 2015' के अनुसार यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा जैविक बाजार यूके है, जिसकी वर्ष 2013 में यूरोप की कुल जैविक बिक्री में 8.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही थी. वर्ष 2013 में यूके का जैविक बाजार 2.1 बिलियन यूरो का था. वर्ष 2007 से 2013 के बीच आर्थिक मंदी और कम जैविक उत्पादन के कारण यूके में जैविक उत्पादों की बिक्री में 3.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से गिरावट आई और जैविक बाजार की कीमत भी 2007 के 2.6 बिलियन यूरो से गिरकर 2013 में 2.1 बिलियन यूरो तक जा पहुंची.

एफआईबीएल तथा आईएफओएएम के एक अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड यूरोप का पांचवां सबसे बड़ा जैविक उत्पाद बाजार है. वर्ष 2013 में विश्व स्तर पर जैविक खाद्य पदार्थों में उच्चतम प्रति व्यक्ति खपत (210 यूरो प्रति व्यक्ति) स्विट्ज़रलैंड की रही. वर्ष 2013 में स्विट्जरलैंड का जैविक बाजार 1.69 बिलियन यूरो का रहा.

जापान

जापान का जैविक बाजार अभी पूरी तरह परिपक्व चरण में नहीं पहुंचा है. यह देश अभी भी अपनी कुल जैविक खाद्य पदार्थों की मांग के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है. हालांकि इससे यह पता चलता है कि यहां जैविक बाजार की विकास क्षमता काफी महत्वपूर्ण है. जापान में आईएफओएएम द्वारा किए गए जैविक बाजार अनुसंधान परियोजना (ओएमआरपी) सर्वेक्षण के अनुसार यहां जैविक खाद्य पदार्थों कि बिक्री समूचे जापानी खाद्य बाजार की मात्र 1 प्रतिशत ही है, जिसकी कीमत वर्ष 2010 में लगभग 1.3 बिलियन यूएस डॉलर से 1.4 बिलियन यूएस डॉलर रही.

संदर्भ: एफआईबीएल

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है. ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं. एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देश के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं. एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो. ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है.

हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है. विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं. एक्ज़िम बैंक अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और सीआईएस क्षेत्रों में 63 देशों को 14.27 बिलियन यूएस डॉलर की 203 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं. इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश पर और उसके सहयोग से जनवरी-मार्च 2016 के दौरान निम्नलिखित ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं:

- गुयाना सरकार को ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट के लिए 50 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई. इसके साथ ही एक्ज़िम बैंक गुयाना को भारत सरकार की ओर से अब तक 94.10 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थांएं प्रदान कर चुका है. इससे पहले 2007 क्रिकेट विश्व कप के लिए जॉर्जटाउन में स्टेडियम निर्माण हेतु, ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट, स्थायी और मोबाइल सिंचाई पंपों और मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई थीं.

- बांग्लादेश को 2 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई. यह ऋण-व्यवस्था बांग्लादेश में विभिन्न सामाजिक और ढांचागत परियोजनाओं (जैसे- बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिपिंग, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों) के लिए प्रदान की गईं. इससे पहले एक्ज़िम बैंक द्वारा बांग्लादेश सरकार को 862 मिलियनयूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था दी गई थी, जो रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, ड्रेजिंग, पुलों के निर्माण, बसों, लोकोमोटिव, कोच की खरीद और सैयदपुर कार्यशाला के पुनरुद्धार के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन, मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
फोन: +91 22 2216 2073 / 2217 2310
फैक्स: +91 22 2218 2460
ईमेल: eximloc@eximbankindia.in

एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता ऋण के जरिए भारत से परियोजना निर्यात बढ़ाने के बैंक के उद्देश्य को संवर्द्धन मिला है. क्रेता ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक ऐसे भारतीय निर्यातकों को सुरक्षित और दायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प मुहैया कराता है जिन्हें मध्यम और दीर्घावधि के आधार पर आस्थगित ऋण की जरूरत होती है और उन निर्यातकों को परंपरागत बाजारों के साथ-साथ विकासशील देशों के नए बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद करता है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक्ज़िम बैंक के जरिए परियोजना निर्यात के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज अनुदान की एक पायलट स्कीम का शुभारंभ किया है. इसका स्वरूप और दिशा-निर्देश मार्च 2013 में मंजूर हो गए थे.

वर्तमान में ईसीजीसी द्वारा 78 देशों की एक सकारात्मक सूची तैयार की गई है, जिनके लिए भारतीय निर्यातक एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण ले सकते हैं. इस सूची को अन्य देशों से परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदन मिलने के आधार पर विस्तारित/संशोधित किया जा सकता है, जैसा कि पहले किया जा चुका है. बैंक ने अब तक 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की 19 परियोजनाओं के लिए कुल 2.1 बिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की है.

भारत और सीएलएमवी देशों को आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरतः सीतारमन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के अनुसार, 'भारत और सीएलएमवी देशों के बीच व्यापार संबंध और गठजोड़ और बेहतर हो सकते हैं इसके लिए और दो प्रमुख सिद्धांत क्षेत्रीय वेल्यू चेन्स के साथ संपर्क और एकीकरण महत्वपूर्ण हैं. सीएलएमवी देशों के साथ भारत का व्यापार 11,000 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं.' त्रिपक्षीय हाईवे, उत्तर-पूर्व में संपर्क, बंदरगाह से संपर्क में सुधार और एक्ट ईस्ट नीति इस दिशा में किए गए प्रयास हैं. मंत्री महोदया ने कहा कि भारतीय बैंकों को विदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित करने और परियोजना विकास निधि के प्रस्ताव की जरूरत थी, जो सीएलएमवी देशों में विनिर्माण इकाइयों और शुल्करहित टैरिफ के लिए महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है. जब वैश्विक एफडीआई में गिरावट आई है, पिछले वर्ष भारत ने एफडीआई में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो भारत में निवेशकों का भरोसा दिखाती है. उन्होंने यह भी कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट के इस दौर से दोबारा उबरने के लिए सीएलएमवी देशों और भारत पर निर्भर करेगा.

अगरतला और आइजवाल में शहरी सेवाएं सुधारने के लिए एडीबी ने किया 80 मिलियन यूएस डॉलर का करार

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने दो उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों में ढांचागत सुधार जारी रखने के लिए 80 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं. यह ऋण उत्तर पूर्व क्षेत्र रजधानी विकास निवेश कार्यक्रम के अतंर्गत 200 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तपोषण सुविधा की तीसरी किस्त है. इसका इस्तेमाल अगरतला और आइजवाल में जल आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए किया जाएगा. इससे शहरी सुधारों में भी सहयोग मिलेगा और दोनों शहरों में करीब दस लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा. पिछली किस्तों का इस्तेमाल उत्तर पूर्व के अन्य पांच शहरों शिलांग (मेघालय), आइजवाल (मिजोरम), कोहिमा (नगालैंड), गंगटोक (सिक्किम) और अगरतला (त्रिपुरा) के लिए दिया गया था.

भारत का रक्षा निर्यात 2 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्यः मनोहर पर्रीकर

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात को मौजूदा 330 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर दो बिलियन यूएस डॉलर करना है और इस क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी बनाते समय सरकार इसका खयाल रखेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणाम मिलने लगे हैं और कहा कि मुझे लगता है कि हम इस साल 140-150 मिलियन यूएस डॉलर से 330 मिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गए हैं. हमने निर्यात दोगुना कर दिया है. मैंने अपने लिए लक्ष्य तय किया है कि अगले दो वर्षों में 2 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े तक क्यों न पहुंचा जाए. यह कोई असंभव लक्ष्य नहीं है.

जनवरी-मार्च 2016 में चाय का निर्यात बढ़ा

2016 की पहली तिमाही में देश के चाय निर्यात में मात्रात्मक और मूल्य के लिहाज से वृद्धि दर्ज की गई. टी बोर्ड भारत द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी, फरवरी और मार्च 2016 में मात्रा के लिहाज से निर्यात 6.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मूल्य के लिहाज से 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. डाटा के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर इकाई कीमत निर्धारण 6.6 प्रतिशत रहा. इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में मात्रा और मूल्य के लिहाज से क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में इकाई मूल्य निर्धारण मात्र 1.5 प्रतिशत रहा. दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें तो निर्यात की मात्रा में 4.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मूल्य के लिहाज से 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

पांच साल में चौगुना हुआ चांदी के गहनों का निर्यात

ऐसे समय में जब वैश्विक लग्जरी बाजार ग्राहकों को लुभाने के लिए संघर्षरत है, भारत से चांदी के गहनों का निर्यात बीते पांच वर्षों में आसमान छू गया है. शीर्ष व्यापार संस्था जेम्स एंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का चांदी के गहनों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2010-11 के 566 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 2959 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया. वित्तीय वर्ष 2014-15 से चांदी के आभूषणों के निर्यात में 44 प्रतिशत की उछाल आई है. चांदी के गहनों के निर्यात में वृद्धि से भारतीय डिजाइनरों के लिए थाईलैंड, चीन और तुर्की जैसे मौजूदा अग्रणी देशों से प्रतिस्पर्द्धा के अवसर खुल गए हैं. कम कीमत और बढ़ते ग्राहक भरोसे ने ग्राहकों को खरीद वापसी की गारंटी के साथ स्वर्ण आभूषणों का विकल्प प्रदान किया है. इन सभी कारकों से परिणामतः भारत से चांदी के गहनों का आयात बढ़ा है.

भारत और अर्मेनिया ने किए दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

भारत सरकार और अर्मेनिया सरकार ने मौजूदा दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन संबंधि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. यह प्रोटोकॉल भारत और अर्मेनिया के बीच 9 सितंबर 2004 से अस्तित्व में आए दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन करता है. यह प्रोटोकॉल कर उद्देश्यों के लिए सूचना के आदान-प्रदान संबंधी अनुच्छेद में संशोधन करता है, ताकि इसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) मॉडल के अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके. इसके जरिए दोहरा कराधान परिहार समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हो सकेगा. फलस्वरूप कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

विदेश मंत्री ने एक्ज़िम बैंक के शीर्ष प्रबंधन से की चर्चा

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने शनिवार 30 जनवरी, 2016 को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का दौरा किया. श्रीमती स्वराज को बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं जैसे विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम, परियोजना निर्यात वित्त, राष्ट्रीय बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (एनईआईए), ऋण व्यवस्था (एलओसी) और सलाहकारी सेवाओं आदि के जरिए निर्यात बढ़ाने और निर्यात को सुगम बनाने के लिए बैंक द्वारा किए गए हालिया प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी गई.

शीर्ष प्रबंधन से चर्चा के दौरान श्रीमती स्वराज ने भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में एक्ज़िम बैंक के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने इस बात को विशेष रूप से नोट किया कि एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं की मदद से भारतीय निर्यातकों को काफी लाभ हुआ है और वे कई नए तथा गैर पारंपरिक बजारों में अपनी पैठ बनाने में सफल हुए हैं.

दिसंबर 2015 में भारत सरकार द्वारा ऋण-व्यवस्थाओं के संबंध में जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में ऋण-व्यवस्था प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया गया है और परियोजना की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी बनाया गया है, ताकि उद्देश्य ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत से बेहतरीन परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं का निर्यात हो सके. इसे लोगों द्वारा काफी सराहा गया है.

एक्ज़िम बैंक ने एनईआईए के अंतर्गत श्रीलंका को क्रेता ऋण प्रदान किया

एक्ज़िम बैंक ने श्रीलंका में जल क्षेत्र परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अंतर्गत श्रीलंका के राष्ट्रीय जल आपूर्ति तथा जल निकास बोर्ड के साथ 08 मार्च, 2016 को 403.01 मिलियन यू एस डॉलर के तीन क्रेता ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए. श्रीलंका को प्रदान की गई उक्त सहायता राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत शामिल है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है एवं इसका परिचालन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है. एनईआईए ट्रस्ट (भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है) बैंकों के क्रेता ऋण संव्यावहारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है तथा विदेशी क्रेताओं को भारत से परियोजना निर्यातों के लिए भुगतान करने में मदद करता है. भारत के निर्यातों को बढ़ावा देने के अलावा, एक्ज़िम बैंक का बीसी- एनईआईए कार्यक्रम उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने में भी मदद करता है.

एक्ज़िम बैंक ने आंध्र प्रदेश से निर्यात को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

एक्ज़िम बैंक तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर तथा आंध्र प्रदेश सरकार के औद्योगिक संवर्द्धन सचिव एवं आयुक्त श्री शमशेर सिंह रावत द्वारा हस्ताक्षर किए गए. एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए आंध्र प्रदेश के निर्यातकों की उचित भागीदार तलाशने और बाजार तक पहुंच को सुगम बनाकर निर्यात बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा. इसके अलावा बैंक क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और शोध गतिविधियों के जरिए उनके कौशल विकास में मदद करेगा, जिससे निर्यातकों को चुनिंदा व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी करने में मदद मिलेगी.

एक्ज़िम बैंक ने 3.125% प्रतिवर्ष की कूपन दर पर 5.5 वर्ष के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए

एक्ज़िम बैंक ने 13 जनवरी, 2016 को 5.5 वर्ष की अवधि के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर का अपना रेग एस बॉन्ड निर्गम सफलतापूर्वक जारी किया. इस निर्गम ने 1.25 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया तथा निर्गम को 110 से ज्यादा निवेशकों से 2.5 गुना से अधिक का अभिदान मिला. इस निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि को विदेशों में भारतीय परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण और दीर्घावधि वाले भारतीय विदेशी निवेशों के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 5.5 वर्ष की अवधि वाले इस 500 मिलियन यूएस डॉलर के यूरोडॉलर बॉन्ड को यूएस ट्रेजरी दर से 165 आधार बिंदु ऊपर 3.125% की फिक्स्ड कूपन दर पर जारी किया गया. वर्तमान भू राजनैतिक स्थितियों, घटते क्रूड ऑयल मूल्यों, अनिश्चित इक्विटी मार्केट और अत्यंत अस्थिर बाजार स्थितियों में यह एक प्रतिस्पर्द्धी दर (एन आई पी) है. इस दर पर जारी इस बेंचमार्क साइज के बॉन्ड ने भारत से और अधिक कंपनियों द्वारा बॉन्ड जारी करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. सिटी ग्रुप, जेपी मोर्गन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस निर्गम के लिए लीड मैनेजर और बुक रनर थे. स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा एक्ज़िम बैंक को बीबीबी- तथा मूडीज द्वारा बीएए3 की रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत सरकार की रेटिंग के समान है.

एक्ज़िम बैंक ने निर्यात-आयात बैंक मलेशिया बर्हाद के साथ किया एमओयू

भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा निर्यात-आयात बैंक मलेशिया बर्हाद ने दोनों बैंकों के लिए लाभप्रद परियोजनाओं के वित्तपोषण, गारंटी एवं अन्य वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. इस एमओयू के जरिए दोनों संस्थाएं भारतीय कंपनियों को मलेशिया में परियोजनाएं स्थापित करने तथा मलेशियाई कंपनियों को भारत में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु निधिक सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद करेंगी. इस एमओयू के अंतर्गत दोनों संस्थाएं अन्य अल्पविकसित देशों में भी भारतीय तथा मलेशियाई कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान करेंगी. इन देशों में दोनों संस्थाएं अपने विशिष्ट अधिदेशों के अनुसार आर्थिक सहयोग तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी. इस एमओयू के अंतर्गत भारत एवं मलेशिया के नियमों, अधिनियमों एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय मुद्रा में पात्र परियोजनाओं को परियोजना वित्त, उपकरण वित्त, निर्यात एवं आयात वित्त, विदेशी निवेश वित्त आदि वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संभाव्यता का भी पता लगाया जाएगा.

भारतीय चमड़ा उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया है. 60 और 70 के दशक में जो उद्योग महज़ कच्चे माल का निर्यातक था, वह आज तैयार और मूल्य वर्द्धित चमड़ा उत्पादों का निर्यातक है. इस उद्योग ने खुद को अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू बाजार में भी एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में स्थापित किया है और अब चमड़े के प्रमुख वैश्विक निर्यातकों में शामिल है.

भारतीय चमड़ा उद्योग के खंड

चमड़ा उद्योग में चमड़ा शोधन कारखाने (जहां पशुचर्म और त्वचा को चमड़े में बदला जाता है) और विनिर्माण इकाइयां (जहां चमड़े के जूते-चप्पल, वस्त्र, आउटरवेयर और चमड़े के विभिन्न सामान बनाए जाते हैं). ये उत्पादन सुविधाएं प्रमुख रूप से असंगठित क्षेत्र में फैली हैं, जिसका कुल उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत योगदान है.

चमड़े के फुटवेयर और पुर्जे

फुटवेयर यानी जूते-चप्पल के क्षेत्र को चमड़ा उद्योग के विकास का इंजन माना जाता है. 2013-14 में भारत चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक देश था, जिसका विश्व के कुल फुटवेयर उत्पादन में 11.6 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

फुटवेयर प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता में लगातार कई वर्षों से होते सुधार के साथ भारतीय फुटवेयर उद्योग ने वैश्विक फुटवेयर व्यापार में अपने क्लास और कौशल की छाप छोड़ी है. भारत में फुटवेयर उद्योग का विकास बाजार संचालित रहेगा और इसका रुख यूरोपीय संघ तथा अमेरिकी बाजारों की ओर रहेगा.

चमड़े का सामान

2013-14 में चमड़े के सामान की उत्पादन क्षमता सालाना 63 मिलियन नगों की थी. चमड़े का सामान बनाने वाली अधिकांश इकाइयां कोलकाता, चेन्नै, मुंबई, कानपुर, बैंगलोर और पुड्डुचेरी में स्थित हैं. यद्यपि उद्योग की मौजूदगी कुछ अन्य क्लस्टरों में भी है.

भारत चमड़े के सामान और एसेसरीज़ (दस्तानों सहित) का विश्व में पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है. दस्तानों सहित चमड़े के सामान और एसेसरीज़ में भारत का निर्यात 2014-15 में 1453.3 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया था, जो भारत के कुल चमड़ा व चमड़ा उत्पादों के निर्यात का 22.4 प्रतिशत है.

तैयार चमड़ा

भारत में तैयार चमड़ा उत्पादों में (पोलिश, ग्लेज्ड, एनिलाइन, पेटेंट) मैट सरफेस (स्वैड, तुबुक), नप्पा बर्निश्ड और ऑइली लेदर, क्रैकल्ड और डिस्ट्रेड फिनिश आदि शामिल हैं. 2014-15 के दौरान चमड़ा क्षेत्र से देश के कुल निर्यात में भारत के तैयार चमड़े का निर्यात 20.5 प्रतिशत रहा था.

चमड़े के वस्त्र

भारत चीन के बाद चमड़े के परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. भारत में चमड़े के परिधानों की उत्पादन क्षमता 2013-14 में अनुमानित सालाना 16 मिलियन नगों की थी, जो कुल वैश्विक उत्पादन की 13 प्रतिशत है.

घोड़े का साज़ सामान

घोड़े की साज-सज्जा के सामान का भारतीय उद्योग अब वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी हो रहा है और डिजाइन के साथ ब्रांड का प्रभुत्व बन रहा है. घोड़े की साज-सज्जा के सामान के मामले में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है. प्रौद्योगिकी, शिल्पकारिता, उत्पादों की गुणवत्ता घोड़ों की साज-सज्जा के सामान के भारतीय उद्योग की पहचान हैं.

भारत का चमड़ा निर्यात

2014-15 में चमड़े और चमड़े से विनिर्मित सामान का कुल निर्यात 6494.4 मिलियन यूएस डॉलर रहा था. चमड़े के निर्यात में चमड़े के फुटवेयर का स्थान सबसे ऊपर है, जिसका 45 प्रतिशत हिस्सा रहा. चमड़े के अन्य उपखंडों में चमड़े का सामान (22 प्रतिशत), तैयार चमड़ा (21 प्रतिशत), चमड़े के वस्त्र (9 प्रतिशत) और घोड़े की साज-सज्जा का सामान (3 प्रतिशत) शामिल हैं **(टेबल)**.

चमड़े और चमड़े के उत्पादों का निर्यात बीते दो दशकों के दौरान बढ़ता गया है. यह 1990-91 के 1.42 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2010-11 में 4 बिलियन यूएस डॉलर और 2014-15 में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया. यह आज देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाले शीर्ष 10 उद्योगों में शामिल है.

चमड़े और चमड़े के उत्पादों के लिए जर्मनी भारत का सबसे बड़ा बाजार है, जिसे 2014-15 में 12.3 प्रतिशत निर्यात किया गया. अन्य प्रमुख बाजारों में अमेरिका (11.8 प्रतिशत), यूके (11.6 प्रतिशत), इटली (7.8 प्रतिशत), हांगकांग (6.5 प्रतिशत), फ्रांस (5.7 प्रतिशत), स्पेन (5.4 प्रतिशत) और नीदरलैंड (3.5 प्रतिशत) शामिल रहे. 2014-15 में चमड़े और चमड़े के उत्पादों का भारत के कुल निर्यात का दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों को निर्यात किया गया.

संभावनाएं

चमड़ा उद्योग में निर्यात और घरेलू खुदरा बाजार दोनों लिहाज से विकास की अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्ग के लिए और अधिक रोजगार पैदा करने के विपुल अवसर हैं. इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में इसकी निर्णायक भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने चमड़ा उद्योग को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया है

टेबलः चमड़े और चमड़ा उत्पादों का भारत का निर्यात

चमड़ा खंड	2010-11 (मिलियन यूएस डॉलर)	2014-15 (मिलियन यूएस डॉलर)	% हिस्सा	सीएजीआर (%)
चमड़े का माल	855.8	1453.3	22.4	14.2
तैयार चमड़ा	841.1	1329.1	20.5	12.1
चमड़े के वस्त्र	425	604.3	9.3	9.2
घोड़े की साज-सज्जा का सामान	87.9	162.7	2.5	16.6
कुल	3968.7	6494.4	100.0	13.1

स्रोतः एनआईएसएटी

पश्चिम बंगाल की सीमा पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल से सटी है और भूटान और उत्तर-पूर्वी हिस्से के लिए यह राज्य प्रवेश द्वार का काम करता है. पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2014-15 में 132.9 बिलियन यूएस डॉलर आकलित किया गया. राज्य का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2004-05 के 555 यूएस डॉलर की तुलना में 2014-15 में 1,450 यूएस डॉलर रहा, जिसमें 2004-05 और 2014-15 के बीच 10.8 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई. 2014-15 में तृतीयक क्षेत्र ने राज्य के जीएसडीपी में 60.2 प्रतिशत का योगदान दिया, इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान (24.9 प्रतिशत) रहा और फिर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान (14.9 प्रतिशत) रहा. 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान तृतीयक क्षेत्र 12.1 प्रतिशत की सीएजीआर से सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल रहा. यह वृद्धि व्यापार, होटलों, रियल एस्टेट, वित्त, बीमा, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं में दर्ज की गई. 2004-05 और 2014-15 के बीच प्राथमिक क्षेत्र 10.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा. इसी अवधि के दौरान द्वितीयक क्षेत्र 7.7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा. इसमें वृद्धि विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति के चलते रही. 2014-15 में पश्चिम बंगाल से निर्यात 9 बिलियन यूएस डॉलर रहा. निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में मोती और आभूषण, लौह एवं इस्पात, चाय आदि शामिल रहे.

पश्चिम बंगाल और उभरती क्षेत्रीय संबद्धताएं: सहयोग का लाभ उठाने की संभाव्यता

पश्चिम बंगाल की सीमा से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मार्ग निकलते हैं. भले ही वह समुद्री मार्ग हो या सड़क मार्ग और इसलिए यह राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश की जमीन होने के साथ बहुपक्षीय व्यापार और निवेश के नियमों में बदलाव जारी हैं और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है. सभी देश आज सड़क और जलमार्गों के जरिए एक-दूसरे से अधिकाधिक संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं.

पश्चिम बंगाल कई ऐसे देशों से सटा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों का हिस्सा हैं। साथ ही यह राज्य उन देशों के लिए प्रवेशद्वार का काम करता है, जो क्षेत्रीय पहलों का हिस्सा हैं और भारत उन पहलों का एक हस्ताक्षरी है. इन पहलों में बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार(बीसीआईएम) कॉरिडोर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिमस्टेक) और आशियान त्रिपक्षीय हाईवे शामिल हैं.

क्षेत्रीय निर्यात केंद्र के रूप में पश्चिम बंगाल की क्षमता

पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है. यह न सिर्फ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का प्रवेशद्वार है, बल्कि देश के पूर्वी राज्यों के विकास की धुरी बनने की भी क्षमता रखता है. कृषि योग्य विपुल भूमि, स्टील उत्पादन की जबरदस्त क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता और बढ़ते आईटी उद्योग के साथ यह राज्य देश के पूर्वी हिस्से के निर्यात केंद्र के रूप में उभर सकता है.

टेबलः चमड़े और चमड़ा उत्पादों का भारत का निर्यात

भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	88752
प्रशासनिक जिले	19
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति)	1028
कुल जनसंख्या (मिलियन)	91.3
पुरुष जनसंख्या (मिलियन)	46.9
स्त्री जनसंख्या (मिलियन)	44.4
साक्षरता दर (%)	77.1

स्रोतः जनगणना 2011

एक्ज़िम बैंक का अध्ययन 'पश्चिम बंगाल से निर्यातः संभावनाएं एवं रणनीति' चाय, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे राज्य में परंपरागत रूप से मजबूत उद्योगों तथा इनके और अधिक मजबूत होने की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है. इस अध्ययन में रोजगार सृजन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास और ऐसे उत्पादों की घरेलू खपत के साथ-साथ विदेशों में निर्यात पर भी जोर डाला गया है.

यह राज्य अंतरराष्ट्रीय करारों (भारत के पूर्वी हिस्सों को जोड़ने वाले) की संख्या, भारत जिनका हिस्सा है, को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाभ पहुंचा सकता है और खुद को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है.

यह ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि व्यापार के बड़े करारों के साथ वैश्विक व्यापार का मौहाल बदल रहा है, जिससे विनिर्माण का परिदृश्य भी बदल सकता है और इस प्रकार राज्य में उत्पादन प्रक्रियाओं को भी वैश्विक वेल्यू चेन के अनुरूप बनाने की जरूरत है.

पश्चिम बंगाल जैसे-जैसे निर्यात तंत्र प्रदान करने की ओर बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ मौजूदा उद्योग ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी होंगे, बल्कि इसकी क्षमता को देखते हुए यह विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश को भी आकर्षित कर सकता है. राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने तथा विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा राज्य में उत्पादित उत्पादों को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी.

उम्मीद की जा रही है कि इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सबसे प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन करना होगा, जो पश्चिम बंगाल को भारत के पूर्वी हिस्से में निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और जिसकी वैश्विक स्तर पर जबरदस्त पहचान होगी.

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं गतिविधियां
जनवरी-मार्च 2016

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता के सृजन और संवर्द्धन में तथा उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

बैंक ने उत्तराखंड स्थित सामाजिक उद्यम को अपने हस्तनिर्मित शॉल और स्टोलों के लिए भारत और अमेरिका स्थित ई-कॉमर्स कंपनी से ऑर्डर दिलाने में सहयोग किया. इन ऑर्डरों के जरिए इस सामाजिक उद्यम से जुड़ी महिला बुनकरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सका.

एक्ज़िम बैंक ने सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर देशभर के कई मास्टर शिल्पियों को हरियाणा में फरवरी 2016 में लगे मेले में हिस्सा लेने के लिए सहयोग प्रदान किया। बैंक ने मेले में 15 स्टालों को सहयोग प्रदान किया और कश्मीरी कपड़े, मधुबनी पेंटिंग, मणिपुरी ब्लैक पॉटरी, गोंद पेंटिंग, कोल्हापुरी चप्पल, चेन्नापटना खिलौने, वारंगल कार्पेट, फुलकारी कपड़े, कढ़ाई वाले वस्त्र, बनारसी सिल्क के वस्त्र, पट्टचित्र पेटिंग, जूट के बैग और बिदरी मेटलवेयर तथा वुड कार्विंग और वुड इनले कला की प्रदर्शनियों में सहयोग प्रदान किया.

कर्नाटक से बिदरी मेटलवेयर और कर्नाटक तथा तमिलनाडु से वुड इनले एवं कार्विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले शिल्पियों को सूरजकुंड मेला प्राधिकारियों की ओर से कला निधि और कला श्री पुरस्कार से नवाजा गया. यह पुरस्कार संपूर्ण सूरजकुंड मेले में देशभर से पहुंचे 950 कलाकारों में से मात्र 6 शिल्पियों को प्रदान किया गया.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
सुश्री दीपाली अग्रवाल
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई
फोनः (022) 22172829
ईमेल: mas@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र के कार्यकलाप
जनवरी-मार्च 2016

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र (ईसीएल) देशभर के टियर I और टियर I I शहरों में सक्रियता से सेमिनारों का आयोजन करता रहा है. इन सेमिनारों में भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), कस्टम्स, ईसीजीसी और अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के वक्ताओं ने जानकारी प्रदान की। इस तरह सेमिनारों/कार्यशालाओं ने भारत के व्यापार और निवेश के विभिन्न भागीदारों को एक मंच पर लाने में योगदान दिया और इनमें भारतीय निर्यातकों/आयातकों से जुड़े मसलों को संबोधित किया गया. तिमाही के दौरान ईसीएल ने फिओ के सहयोग से चार सेमिनार किए.

- 'भारत में विदेश व्यापार का संवर्द्धन' विषय पर 11 जनवरी, 2016 को मैंगलोर में सेमिनार.
- 'विदेश व्यापार में अवसर और चुनौतियां' विषय पर 26 फरवरी, 2016 को जयपुर में सेमिनार.
- 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश का संवर्द्धन' विषय पर 11 मार्च, 2016 को वड़ोदरा में सेमिनार.
- 'विदेश व्यापार में अवसर और चुनौतियां' विषय पर 17 मार्च, 2016 को कानपुर में सेमिनार.

आगामी कार्यक्रम

- 'ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश का संवर्द्धन' विषय पर 12 अप्रैल, 2016 को कोच्चि में सेमिनार.
- 'भारत में विदेश व्यापार का संवर्द्धन' विषय पर 26 अप्रैल, 2016 को विजयवाड़ा में सेमिनार.
- 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सुगमीकरण' विषय पर 31 मई, 2016 को सूरत में सेमिनार.
- 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश का संवर्द्धन' विषय पर 10 जून, 2016 को आगरा में सेमिनार.
- 'ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश का संवर्द्धन' विषय पर 22 जून, 2016 को बेंगलुरू में सेमिनार.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :
सुश्री दया चन्द्रहास
महाप्रबंधक
एक्ज़िमिअस शिक्षण केन्द्र तथा राजभाषा
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई
फोन: (022) 22861570/ 22830793
ईमेल:
dayachandrahas@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

टीपीपी एंड इंडियाः इंप्लिकेशंस ऑफ मेगा रीजनल्स फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज़

लेखक : हर्ष वर्द्धन सिंह

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पर वार्ता अक्टूबर 2015 में संपन्न हुई. इससे 12 देशों के लिए नए व्यापार विनियम तय हुए, जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर बड़े प्रभाव के साथ वैश्विक व्यापार में एक चौथाई और विश्व जीडीपी में 40 प्रतिशत हिस्सा है. इस नई व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को परखने वाली हर्ष वर्द्धन सिंह की यह किताब ऐसी व्यापार वार्ताओं के चलते वैश्विक बाजार विकास में आने वाले बदलावों पर नई अंतर्दृष्टि और परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है.

यह किताब वैश्विक बाजार में संचालनात्मक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले बुनियादी पहलुओं और टीपीपी जैसी बड़ी क्षेत्रीय साझेदारियों के चलते व्यापार विनियामक व्यवस्था के संभावित क्रमिक विकास की पड़ताल करती है. इसके साथ ही इन साझेदारियों के भारत पर पड़ने वाले परिमाणात्मक प्रभाव की भी पड़ताल करती है. किताब में टीपीपी और ट्रांसएटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) के चलते अगले डेढ़ दशक में भारत की वास्तविक जीडीपी में 3.4 प्रतिशत की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है. टैरिफ के चलते व्यापार के दिशा परिवर्तन का टीपीपी का नकारात्मक प्रभाव मूल्यांकन में शामिल देशों में भारत पर सबसे ज्यादा पड़ने की आशंका है.

लेखक के अनुसार, टीपीपी संबंधी मानक और देशों के टीपीपी में शामिल होने के साथ वस्तुतः वैश्विक मानक बन सकते हैं और खास तौर पर तब जब अमेरिका टीटीआईपी करार में सफलतापूर्वक समान परिणाम शामिल कर ले.

किताब में भारतीय नीति निर्माताओं से मानकों के लिए घरेलू क्षमता को अपग्रेड करने, व्यापार और निवेश संबंधी विषयों पर चीन के साथ गहन समन्वय और अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी क्षेत्रीय साझेदारियों पर सूचना जुटाने के लिए व्यवस्था स्थापित करने की संस्तुति की गई है.

इथियोपिया:

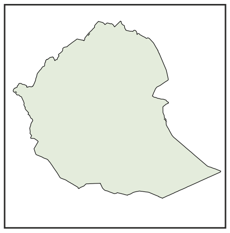

इथियोपिया की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि आधारित है. हालांकि सरकार विनिर्माण, कपड़ा और ऊर्जा उत्पादन की ओर बढ़ रही है. लगातार सूखे और जुताई की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से कृषि क्षेत्र को संकट का सामना करना पड़ता है. तथापि इथियोपिया सरकार और सहयोगियों के हालिया संयुक्त प्रयासों से वहां के कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार आया है, लेकिन विश्वव्यापी मौसमी परिस्थितियों के चलते असामान्य बारिश से लोगों के लिए खाद्य असुरक्षा बनी हुई है. इथियोपिया के उप सहारीय अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने के आसार हैं. हालांकि निर्यात बाजार में गिरावट और असामान्य मांग (खास तौर पर चीन से) और प्रतिकूल मौसम के रूप में देश को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अर्थव्यवस्था में तेजी ढांचागत विकास के रूप में वर्तमान में जारी राजकोषीय तेजी के चलते बने रहने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के अनुसार 2016 में वास्तविक जीडीपी 7.6 प्रतिशत और 2017 में 7.3 प्रतिशत बने रहने की उम्मीद है.

सऊदी अरब :

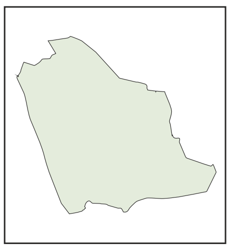

सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल से चलती है और प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का नियंत्रण है. राजस्व का करीब 87 प्रतिशत, जीडीपी का 42 प्रतिशत और निर्यात आय का 90 प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम क्षेत्र से ही आता है. सऊदी अरब ने 'सऊदी विज़न 2030' शीर्षक से दीर्घावधि आर्थिक ब्लू प्रिंट जारी किया है, जिसमें विनियामक, बजट और नीतिगत बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्हें अगले 15 वर्षों में सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता कम करने की उम्मीद के साथ लागू किया जाना है (उद्देश्य 2030 तक गैर-तेल जीडीपी में गैर-तेल निर्यात का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करना है). आर्थिक विकास 2016-20 के दौरान मंद रहने की आशंका है, क्योंकि राजकोषीय मितव्ययता, सपाट तेल उत्पादन और निवेश में गिरावट के चलते विस्तार की गति मंद पड़ी है.

चिलीः

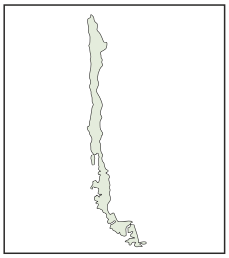

चिली की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक से लैटिन अमेरिका की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है. हालांकि निवेश चक्र खत्म होने के चलते खनन क्षेत्र में आई मंदी और तांबे की कीमतों व निजी खपत में आई गिरावट के कारण इसकी जीडीपी विकास दर 2014 में 1.9 प्रतिशत और 2015 में 2.1 प्रतिशत गिरी है. निजी क्षेत्र में सुधार के साथ विकास दर में भी सुधार आने की उम्मीद है. तांबे की कम कीमतों और घरेलू मांग कम होने की वजह से 2016 में विकास की रफ्तार धीमी रहने के आसार हैं.

आर्थिक मंदी, तांबे की कीमतों में गिरावट और विस्तारपरक नीतियों के क्रियान्वयन के चलते राजकोषीय घाटा बढ़ गया. 2015 में कर सुधार के बावजूद घरेलू मांग कम रहने के चलते कर राजस्व में कमी आई और केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन 2013 के जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के सरप्लस से 2015 में 2.1 प्रतिशत घाटे में तब्दील हो गया.

चीनः

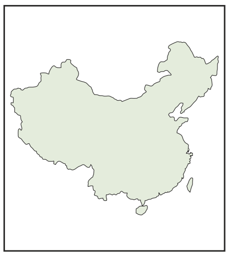

1978 में आर्थिक सुधार प्रारंभ होने के बाद चीन दुनिया का विनिर्माण केंद्र बन गया. तथापि, हाल के वर्षों में चीन के आधुनिकीकरण से तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और 2013 में डीजीपी में इसका योगदान सबसे ज्यादा 46.1 प्रतिशत हो गया, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा देश के संपूर्ण उत्पादन में अब भी 45.0 प्रतिशत है. इस बीच, चीन के दरवाजे दुनिया के लिए खुलने के बाद से उसकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान नाटकीय रूप से घटा है.

चीन की धीमी विकास दर की कई वजहें हैं, मसलन- जरूरत से ज्यादा ऋण, औद्योगिक अतिक्षमता, सरकारी बैंकों द्वारा पूंजी का अपर्याप्त वितरण और चीन के व्यापारिक भागीदारों से धीमी रिकवरी. 2015 में जारी सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार जारी रखने और नवोन्मेष तथा घरेलू खपत को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, ताकि भविष्य में स्थायी निवेश, निर्यात और भारी उद्योग पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम की जा सके.

वियतनामः

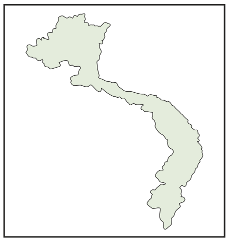

राजनीतिक और आर्थिक सुधारों (डोइ-मोइ) ने वियतनाम को दुनिया के सबसे गरीब देशों की फहेरिस्त से निकालकर 25 साल के भीतर ही निम्न मध्य आय वाले देशों में शामिल कर दिया. 2015 के अंत तक इसकी प्रति व्यक्ति आय 2100 यूएस डॉलर थी. वियतनाम की प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर 1990 से ही दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दरों में शामिल रही है. यह 1990 से हर साल औसतन 5.5 प्रतिशत और 2000 के दशक में 6.4 प्रतिशत रही. वियतनाम की अर्थव्यवस्था 2015 में 6.7 प्रतिशत की आकलित जीडीपी विकास के साथ सालभर मजबूत बनी रही.

वियतनाम की अर्थव्यवस्था के जबरदस्त निजी खपत और उच्चतर एफडीआई आवक से लगातार बढ़ते रहने की उम्मीद है. लेकिन प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते विकास दर कम होने का खतरा भी बना हुआ है.

जापानी येन

बैंक ऑफ जापान ने 29 जनवरी को अपनी बैठक में क्यूक्यूई प्रोग्राम को जारी रखने संबंधी अपने निर्णय के अनुक्रम में कतिपय राशियों से ऊपर वाले चालू खातों के ऊपर ऋणात्मक ब्याज दर जारी रखने के बाद से अपनी मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

इसके साथ ही बैंक ऑफ जापान ने बैंक द्वारा निर्धारित 2 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त न होने पर नीति निर्माताओं को दूसरे चरण के मौद्रिक विस्तार कार्यक्रम के लिए भी तैयार रहने को कहा है। बाजार का अनुमान है कि बैंक इस लक्ष्य को शायद पूरा नहीं कर पाएगा और जापान को एक और मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज लाना पड़ेगा।

तथापि बैंक ऑफ जापान कोई भी नया उपाय करने के पूर्व जो केंद्रीय बैंक में वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त जमा राशि पर - 0.1 प्रतिशत की ब्याज दर संबंधी कुछ महीने पहले लागू किए गए नीतिगत कदम के असर का विश्लेषण करेगा. अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज पॉलिसी ब्याज दरों को और नकारात्मक क्षेत्र में ले जाएगा.

फरवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 0.0 प्रतिशत से बढ़कर 0.3 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष हो गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति 0.0 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष ही रही. इससे गिरती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार पर आर्थिक विकास दर बढ़ाने वाली नीतियां अपनाने का दबाव बनेगा.

यद्यपि व्यापार के आधार पर येन डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत जरूर हुआ, लेकिन फरवरी में तेजी से बढ़ने के बावजूद मार्च में यह 1.4 प्रतिशत गिर गया. बाजार का अनुमान साल के अंत तक यूएस डॉलर के मुकाबले जापानी येन के 110.0 के आसपास रहने का है. 31 मार्च, 2016 तक एक यूएस डॉलर की कीमत 112.56 जापानी येन के समतुल्य थी.

रूसी रूबल

हाल में कच्चे तेल की कीमतें कुछ संभलने के बाद रूसी रूबल यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, जिससे निम्नतर समायोजन के अब पूरा होने की दोबारा उम्मीद बनी है. लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन (सीबीआर) इस बात से सहमत नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और रूबल में मजबूती का यह दौर जारी रहेगा.

यदि रूबल में यह मजबूती बनी रहती है तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ने के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे सीबीआर को इस साल की दूसरी छमाही में ब्याज दरें घटाने में आसानी होगी. सीबीआर ने संकेत भी दिए हैं कि वह निकट भविष्य में कमजोर रूबल को मजबूत करने के प्रयास नहीं रोकेगा. यदि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं तो इससे रूस के आर्थिक विकास की रफ्तार घटने के खतरे को भी कम किया जा सकता है. बाजार को आशंका है कि रूसी अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार इस साल -1.5 प्रतिशत तक और कम होगी, जो पिछले साल -3.7 प्रतिशत थी. वास्तविक खुदरा बिक्री के लिए वार्षिक संकुचन दर फरवरी में कम होकर -5.9 प्रतिशत रही और गौर करने वाली बात है कि औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक दर साल में पहली बार सकारात्मक हुई. तेल कीमतें कम होने पर सरकार द्वारा खर्च में की गई कटौती से कड़ी राजकोषीय नीति और आर्थिक प्रतिबंध लागू रहने से आर्थिक विकास धीमा पड़ेगा. ऐसी परिस्थितियों में कच्चे तेल की कीमतों में धीरे-धीरे होने वाले सुधार से बाजार को आने वाले साल में रूबल के मजबूत होने की उम्मीद है. 31 मार्च, 2016 तक एक यूएस डॉलर 66.97 रूबल के समतुल्य था.

भारतीय रुपया

लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद भारतीय रुपया मार्च में डॉलर के कमजोर रहने से कुछ संभला. डॉलर कमजोर हुआ क्योंकि फेडरेशन ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने ब्याज दरों के बढ़ाने की संभावना को चार बार से घटाकर दो बार कर दिया. यह 29 फरवरी को बजट बाद की घोषणा से निवेशकों के रुख में हुए सुधार के अतिरिक्त था, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरें घटाने को लेकर बाजार की उम्मीदें और बढ़ गईं और इक्विटी में अच्छा खासा निवेश हुआ. इक्विटी में शुद्ध विदेशी संस्थागत निवेश मार्च में 3.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो लगातार दो महीनों की निवल जावक और जनवरी 2015 के बाद से सबसे बड़ी आवक रही. बाजार रुपये की इस मजबूती को अस्थायी मानता है, क्योंकि अगली तीन तिमाहियों में रुपये के कुल मिलाकर कमजोर रहने की आशंका है. ऐसा इसलिए है क्योंकि एफओएमसी जून में ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है और ब्रेक्ज़िट से उभरने वाला जोखिम भी बना हुआ है. तथापि फेडरल रिज़र्व सिस्टम (एफईडी) द्वारा 2016 में ब्याज दरें बढ़ाने डॉलर के पिछले साल जितना मजबूत बने रहने की संभावना कम ही है. इसका मतलब होगा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूती पकड़ेगा.

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा गहनों पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के बाद सोने की मांग में आई कमी से व्यापार घाटा भी कम हो सकता है. सरकार के राजकोषीय मजबूती जारी रखने और हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में जनवरी की 5.69 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष वृद्धि से फरवरी में 5.18 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष धीमी वृद्धि के चलते आरबीआई 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति में नरमी बरत सकता है. 31 मार्च 2016 तक 1 डॉलर 66.25 भारतीय रुपये के समतुल्य था.

डॉ. डोनाल्ड कबेरुका ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का 31वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया। अफ्रीकी विकास बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में हॉजर लीडर इन रेजिडेंस डॉ. डोनाल्ड कबेरुका ने 21 मार्च, 2016 को मुंबई में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का 31वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया. अफ्रीकी विकास बैंक में नियुक्ति से पहले डॉ. काबेरुका रवांडा के वित्त मंत्री थे. उन्होंने 'नए वैश्विक परिदृश्य में भारत-अफ्रीका निवेश को बढ़ावा' विषय पर अपना व्याख्यान दिया.

एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर ने कहा कि 1986 में शुरू हुई एक्ज़िम बैंक की स्थापना दिवस व्याख्यान माला ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले समसामयिक व्यापार और विकास के मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है. डॉ. सुनील अरोड़ा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

डॉ. कबेरुका ने अपने व्याख्यान में अफ्रीका और भारत की विकास यात्रा पर विस्तार से बात की और नए आर्थिक परिदृश्य एवं आने वाले समय में दोनों क्षेत्रों के उत्तरोत्तर विकास संबंधी संभावनाओं का उल्लेख किया. अफ्रीका और भारत के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश के प्रवाह को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय संकट में भी यह व्यापार वर्ष 2008 के 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 76 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. इसके साथ-साथ अफ्रीकी अर्थव्यवस्था भी आज वर्ष 2000 की तुलना में 5 गुना बढ़ी है. (वर्ष 2000 के डॉलर की तुलना में तीन गुना).

डॉ. कबेरुका ने इस बात को भी रेखांकित किया कि बीते पचास साल और खास तौर पर इस आधी सदी का अंतिम हिस्सा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अद्भुत रहा है. वैश्वीकरण से इन वर्षों में अरबों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं. कारोबार करने की लागत घटी है. एक-दूसरे से संपर्क बेहतर हुआ है और सभी देशों के लिए अवसर खुले हैं. उन्होंने दावोस में आयोजित पिछली विश्व आर्थिक बैठक में हुई परिचर्चा का जिक्र करते हुए नई आर्थिक व्यवस्था को 'चौथी औद्योगिक क्रांति' की संज्ञा दी और कहा कि इसमें न सिर्फ नए अवसरों की अपार संभावनाएं हैं बल्कि यह परंपरागत व्यवसाय मॉडलों को तोड़ रही है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी विकास की आधुनिक अवधारणाएं भी शामिल हैं.

डॉ. कबेरुका ने कहा कि 'यह भूराजनीति में भी नई घटनाओं का दौर है, जहां समस्याएं वैश्विक हो रही हैं लेकिन राजनेता स्थानीय स्तर के समाधानों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इससे एक बड़ी खाई पैदा हो रही है. द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बनी बहुपक्षीय व्यवस्था अब व्यापार, प्रवासन, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों और जलवायु परिवर्तन जैसे उद्देश्यों पर काम करने के लिहाज से उपयुक्त नहीं रह गई है. भारत और अफ्रीका दोनों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि दोनों क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का लाभ उठाते हुए कैसे नकारात्मक पहलुओं को कम करना है.'

उन्होंने भारत के साथ अफ्रीका की समरूपता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय एवं अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के सिकुड़ने से रोजगार सीमित हुए हैं, असमानता आई है और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण में कमी आई. चूंकि दोनों क्षेत्र लगातार तेजी से विकास कर रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के लिए कृषि व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं सहित ढांचागत विकास जैसे क्षेत्रों में अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

डॉ. कबेरुका ने केन्या और कोत- दि- वार जैसे कुछ भूभागों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में पीपीपी, बीओटी परियोजनाओं की सराहना की, लेकिन कहा कि ये उदाहरण भारत सहित पूरे क्षेत्र में सफलता की कहानियां नहीं बना पाए. उन्होंने ढांचागत विकास के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडल पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के इस साल साथ मिलकर काम करने की योजना की प्रशंसा की.

अपने व्याख्यान में डॉ. कबेरुका ने कहा कि निवेशकों को अफ्रीका को घिसी-पिटी अर्थव्यवस्था नहीं समझना चाहिए तथा अल्पावधि की घटनाओं को अनदेखा करते हुए दीर्घावधि परिदृश्य पर ध्यान लगाना चाहिए. उन्होंने इस महाद्वीप में अतिवाद की मौजूदा समस्याओं पर चिंता जताई, जो निवेश के लिए बड़ी बाधा बना हुआ है. डॉ. कबेरुका ने कहा कि उन्हें लगता है इस समस्या से सशक्त बहुपक्षीय व्यवस्था और सहयोग से निपटा जा सकता है.

चीन में आई मंदी और इसके 'ट्रिपल ट्रांजिशन' फेज का जिक्र करते हुए डॉ. कबेरुका ने कहा, उन्हें लगता है भारत और अफ्रीका दोनों देशों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि प्रतिस्पर्धी बढ़त वाली परिस्थितियां दोनों क्षेत्रों के पक्ष में हैं. वह भारत और अफ्रीका को लेकर बेहद आशावान दिखे. उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों को उनकी युवा और शिक्षित जनसंख्या, बढ़ती उपभोज्य आय और आपसी संबंधों से लंबी अवधि में बड़ा लाभ मिलने वाला है.

एक्ज़िम बैंक की इस वार्षिक व्याख्यानमाला का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण से संबन्धित मुद्दों के बारे में चर्चा और बहस को निरंतर आगे बढ़ाना है। विगत वर्षों में अर्थशास्त्रियों, व्यापार जगत, शैक्षणिक जगत और समाज के अन्य वर्गों से इसको भरपूर समर्थन मिला है और आज एक्ज़िम बैंक की इस वार्षिक व्याख्यानमाला को मुंबई के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1708.5	1823.2	1828.9	1863.9	2041.9	2075.8[f]
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	8.9	6.7	5.6**	6.6**	7.2**	7.6[p]**
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)						
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	18.5	17.8**	17.5**	16.3**	15.3[p]**
उद्योग	27.9	32.5	31.9**	31.5**	31.2**	31.2[p]**
सेवाएं	57.5	49.0	50.3**	51.0**	52.5**	53.5[p]**
मुद्रास्फीति की दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	9.6	8.9	7.4	6.0	2.0	-2.5
मुद्रास्फीति की दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	10.4	8.3	10.2	9.5	6.0	4.9
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9[e]
विनिमय दर (₹. / यूएस डॉलर, औसत)	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5
विनिमय दर (₹. / यूरो, औसत)	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	249.8	306.0	300.4	314.4	310.3	262.0
% परिवर्तन	39.8	22.5	-1.8	4.7	-1.3	-15.6
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	36.4	56.7	60.9	63.2	56.7	30.4
% परिवर्तन	29.0	55.9	7.3	3.8	-10.2	-46.4
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	213.4	249.2	239.5	251.2	253.6	231.6
% परिवर्तन	41.8	16.8	-3.9	4.9	0.9	-8.7
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	369.8	489.3	490.7	450.2	448.0	380.4
% परिवर्तन	28.2	32.3	0.3	-8.3	-0.5	-15.1
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	106.0	155.0	164.0	164.8	138.3	82.9
% परिवर्तन	21.6	46.2	5.9	0.4	-16.0	-40.1
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	263.8	334.3	326.7	285.4	309.7	297.5
% परिवर्तन	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.9
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	-120.0	-183.3	-190.3	-135.8	-137.7	-118.4
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर) *	124.6	140.9	145.7	151.5	156.0	154.3
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर) *	80.6	76.9	80.8	78.5	79.8	84.6
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर) *	44.0	64.0	64.9	73.0	76.2	69.7
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर) *	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-26.8	-22.1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	304.8	294.4	292.0	304.2	341.6	360.2
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	317.9	360.8	409.4	446.2	475.0	485.6
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	18.2	21.1	22.4	23.8	23.8	23.7
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2
कुल ऋण सेवा अनुपात (%)	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8
एफ डी आई (बिलियन यूएस डॉलर)	36.0	46.6	34.3	36.0	45.1	55.4
जीडीआर / एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4
एफआईआई (निवल) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-3.5
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	17.2	10.9	7.1	9.2	4.0	8.8

पी- भारत सरकार के अग्रिम अनुमान; ई- भारत सरकार के अनुमान; एफ- आईआईएफ पूर्वानुमान; *- 2009-10 से आंकड़े, आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के मानक प्रस्तुतीकरण के नए फॉर्मैट को अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए हैं; **- संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार आंकड़े

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केंद्रीय बजट, भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक; वित्त मंत्रालय; सीएसओ; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ).

चार्ट 1: भारत का निर्यात: मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

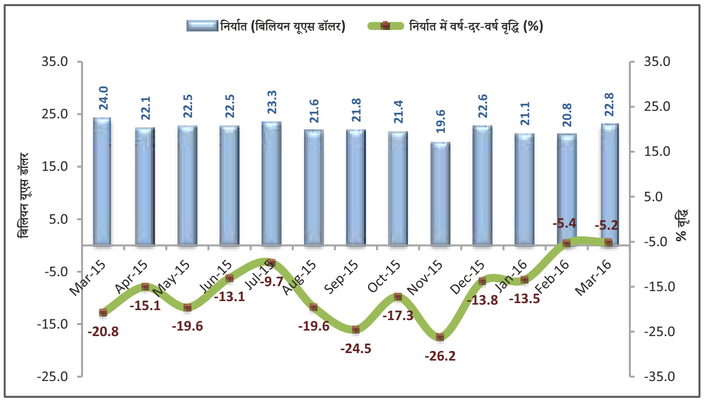

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 2: भारत का आयात: मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

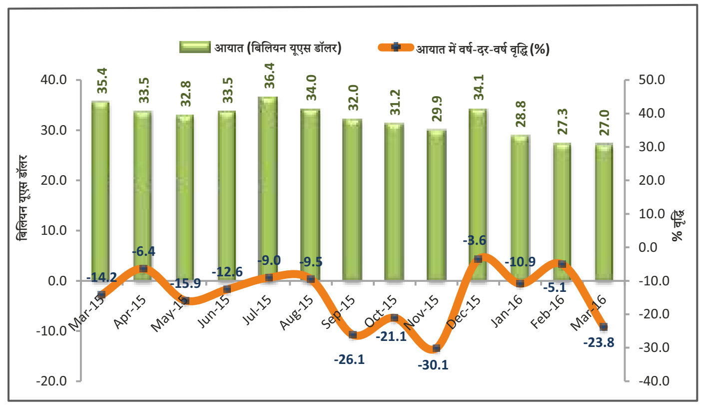

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3: 2015-16 में भारत की निर्यात संरचना

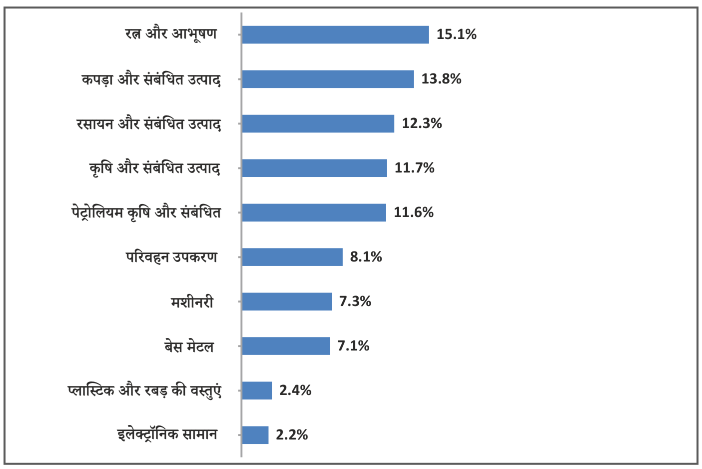

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 4: 2015-16 में भारत की आयात संरचना

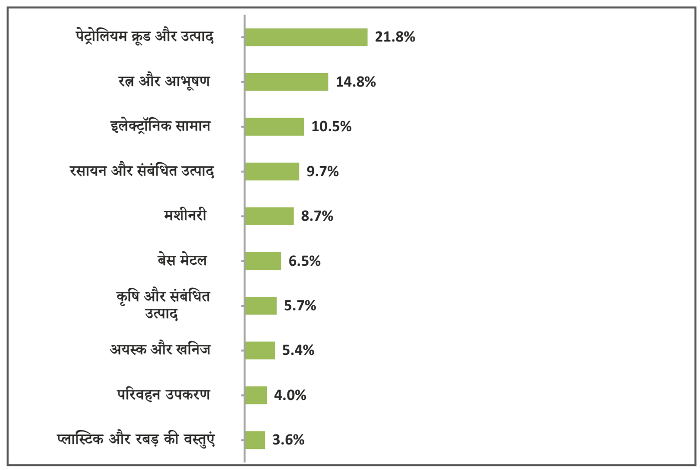

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 5 : भारत के निर्यात स्थल

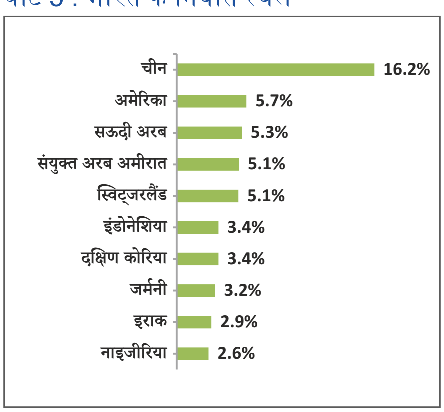

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 6 : भारत के आयात स्रोत

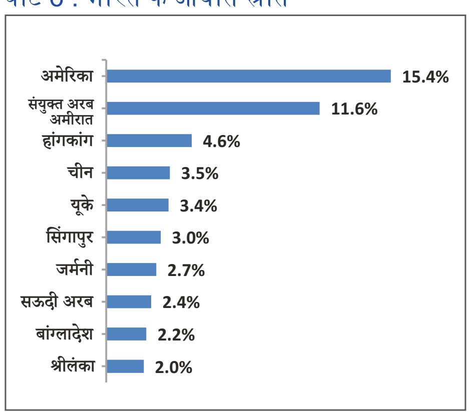

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/ माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रमाणिक हैं. प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है.

नोटः भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है.
1 करोड़: 10 मिलियन
1 लाख: 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई- 400 005
दूरभाषः +91-22-2217 2600
फैक्सः +91-22-2218 2572
ई-मेलः ccg@eximbankindia.in
वेबसाइटः www.eximbankindia.in

संपर्क : अहमदाबाद : 079 2657 6852, बैंगलोर : 080 2558 5755, चंडीगढ़ : 0172 2641 910, चेन्नै : 044 2852 2830, गुवाहाटी : 0361 223 7607, हैदराबाद: 040 2330 7816, कोलकाता : 033 2289 1728, नई दिल्ली : 011 2347 4800, पुणे : 020 2640 3000.
अदिस अबाबा : +251 116-630079, दुबई : +9714-3637462, जोहांसबर्ग : +2711-3265103, लंदन : +44 20 -77969040, सिंगापुर : +65 65-326464,
यांगून : +95 1-389520, वाशिंगटन डी.सी.: +1202-2233238.

व्यापार एवं साझेदारी अवसर

व्यापार अवसर

पेय वेंडिंग मशीन

भारत के शीर्ष वेंडिंग मशीन सेवा प्रदाता द्वारा निर्मित विश्व स्तरीय वेंडिंग मशीन। इसकी विशेषता है कि यह एक साथ शीतल और गर्म पेय जैसे कॉफी, चाय, सूप और आइस टी पेश कर सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं असेसरीज़

एक आई एस ओ 9000 प्रमाणित कंपनी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, लाइटनिंग प्रोटेक्शन और केबल आदि की निर्माता और निर्यातक कंपनी है। कंपनी अपने ग्राहकों को ओईएम ब्रांडिंग और उनकी जरूरत के अनुसार पैकेजिंग समाधान भी उपलब्ध कराती है।

केले के रेशे (बनाना फाइबर) के उत्पाद

दक्षिण भारत में स्थित एक स्वयं सहायता समूह के साथ व्यापार अवसर। यह समूह बनाना फाइबर से स्टेशनरी आइटम और घरेलू उपयोग की चीजें जैसे प्लेसमेंट्स, टेबल रनर, कोस्टर और हैंड बैग आदि बनाता है।

एफएमसीजी और कृषि उत्पाद

कंपनी एफएसएसएआई और एगमार्क प्रमाणित है। कंपनी पापड़, इन्स्टैंट मिक्स, सॉस, केचअप, अचार और पिसे मसाले और अन्य मिश्रण आदि तैयार करती है। कंपनी किसानों को उचित मूल्य देकर कृषि उत्पाद खरीदती है।

चमड़े की कठपुतली पेंटिंग

बारहवीं शताब्दी के आस पास यह कला आन्ध्रप्रदेश में पनपी जिसके जरिए देवताओं की कहानियों को लोगों को सुनाया जाता था। आज यह कला हिन्दू पौराणिक कहानियों के आधार के रूप में एक चित्रकला के रूप में स्थापित हो गई है। इस चित्रकारी में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी रंग प्राकृतिक रंग होते हैं।

डेयरी उत्पाद

यह भारत की अग्रणी चीज निर्माता कंपनी है जो हर प्रकार के चीज का उत्पादन करती है। कंपनी औद्योगिक चेनों, स्टोर्स, ग्राहकों और खुदरा क्षेत्र में आपूर्ति करती है तथा कंपनी के पास 99 निजी लेबल हैं। कंपनी प्रसंस्कृत चीज, मक्खन, दही, दूध, फलों के रस तथा आइस टी जैसे उत्पाद बनाती है।

साझेदारी अवसर

निवेश अवसर

(I) इटली की एक मार्बल कंपनी को एक भारतीय व्यापार भागीदार की तलाश है। कंपनी अपने भागीदार को 30% इक्विटी हिस्सा बेचना चाहती है। 1960 में इटली में शुरू हुई यह कंपनी पूरे विश्व में अपने प्रौद्योगिकी नवाचारों और नए डिडाइनों वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है। कंपनी प्रीमियम बाजार में अच्छी उपस्थिति रखती है।

निर्यात अवसर

- बांग्लादेश के एक सरकारी उपक्रम द्वारा गैस पाइपलाइन के लिए विभिन्न प्रकार के स्टील पाइप की खरीद के लिए टेंडर जारी किया गया है। टेंडर भरने की अंतिम तारीख 14 जून है 2016 है।
- अमेरिका की एक ई-कॉमर्स कंपनी भारत से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की खरीद करना चाहती है।
- औद्योगिक उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर भारतीय निर्यातकों से उनके उत्पादों को अपने ऑनलाइन स्टोर में प्रदर्शित करने का इच्छुक है।

इच्छुक पार्टियां विपणन सलाहकारी सेवाएं समूह को नीचे दिए गए टेलीफोन नं. पर कॉल कर सकती हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें- फोनः 2217 2600 एक्सटेंशनः 2707. फैक्सः 2218 8268 ई-मेलः mas@eximbankindia.in